



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 21 अगस्त, 2009/30 श्रावण, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 जुलाई, 2009

संख्या: आवास-6 (एफ) 5-2/2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक प्राधिकरण है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मौजा दौहन्दी तहसील सदर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में आवास वस्ती के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है ।

2. अतः एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्नलिखित विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

3. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निगम बिहार शिमला-2 को एतद् द्वारा उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है ।

4. भूमि का रेखांक समाहर्ता, भू-अर्जन अधिकारी, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार शिमला-2 हि0 प्र0 के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	मुहाल	खसरा न0	रक्वा
मण्डी	सदर मण्डी	दौहन्दी	114	2-9-10
			115	0-18-10
			116	1-07-17
			117	3-14-04
			958/118	1-13-09
			959/118	2-13-05
			119	1-07-05
			120	1-06-01
			121	0-02-08
			247	0-04-02
			248	1-09-19
			249	0-12-14
			250	0-10-14
			251	0-06-05
			252	3-12-18
			253	0-02-10
			254	2-01-12
			255	5-07-17
			256	0-02-02
			282	0-02-08
			282/1	0-05-12
			1130/284	0-15-08
			1131/284	0-15-12
			1089/285	0-12-12
			1090/285	3-09-06
			286	1-17-05
			287	0-10-10
			288	0-06-09
			289	2-11-18
			290	0-17-00
			291	3-14-00
			292	1-06-18
			1133/293	1-08-15

1132 / 293	1-08-14
294	1-06-08
295	1-06-08
297	1-01-12
298	0-11-11
299	0-03-18
300	0-09-01
301	0-01-12
302	0-17-04
303	1-00-18
304	0-07-04
305	0-03-03
306	1-02-19
307	1-13-05
1120 / 308	0-08-12
1121 / 308	0-07-13
1122 / 308	0-06-13
309	0-06-16
311	1-19-03
311 / 1	1-07-00
1012 / 312	0-03-08
313	0-03-03
314	0-19-16
315	0-12-03
किता-57	67-06-17

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित / -
प्रधान सचिव ।

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 12th August, 2009

No. Shram(B)1-1/2009(Estt.).—The Governor, Himachal Pradesh on the recommendations of the Departmental Promotion Committee is pleased to order the promotion of Sh. R.K. Sandhu, Deputy Labour Commissioner to the post of Joint Labour Commissioner, (Class-I, Gazetted) in the pay scale of Rs. 10025-15100 in the Labour and Employment Department, Himachal Pradesh, on regular basis with immediate effect.

The above officer on his promotion shall remain on probation for a period of one year.

By Order,
MRS. PARMINDER MATHUR,
Addl. C.S. (Lab. & Emp.).

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग**अधिसूचना**

17 अगस्त, 2009

संख्या : विद्युत.-छ-(5)-7/2007.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत एक सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है को अब निम्नलिखित भूमि की आवश्यकता नहीं है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा-48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग द्वारा जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-7-2009 तथा 20-11-2007 जो कि क्रमशः भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा-4 तथा 6 व 7 के अन्तर्गत मुहाल फाटी सुचैहण कोठी वनोगी तथा फाटी शैशर कोठी शैशर उप तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू में सैज जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने के लिये जारी की गई थी में से निम्नलिखित भूमि को अधिग्रहण करने की कार्यवाई सहर्ष वापिस लेते हैं।

विवरणी

जिला	उप तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकबा (बीघों में)
कुल्लू	सैन्ज	फाटी सुचैहण कोठी वनोगी	1802/398	0-5-0
		फाटी शैशर	2944	1-8-0
		कोठी शैशर	2945	0-4-0
			2946	0-8-0
			2947	2-5-0
			2948	0-12-0
			2949	0-2-0
			2950	0-15-0
			2951	0-6-0
			2952	2-14-0
			2953	0-10-0
			2954	0-17-0
			2955	0-9-0
			2956	0-3-0
			कुल कित्ता-14	कुल रकबा-10.18.0 बीघा

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव।

आयुर्वेद विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 11 अगस्त, 2009

संख्या आयु0-ख (15)-6/95-IV.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या आयु0-सी (क) 3-2/94 तारीख 1-8-1996 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, वरिष्ठ प्राध्यापक, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1996 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, वरिष्ठ प्राध्यापक, वर्ग-II (राजपत्रित) सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2009 हैं ।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उपाबन्ध 'अ' का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, वरिष्ठ प्राध्यापक वर्ग-II (राजपत्रित) सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1996 के उपाबन्ध 'अ' में:—

स्तम्भ संख्या 17 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 के उपबन्ध के दृष्टिगत, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट होगी । तथापि, उसे प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, ऐसा न होने पर वह उक्त पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा” ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव ।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Ayur.-Kha(15)-6/95-IV dated 11-08-2009 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

AYURVEDA DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-2, the 11th August, 2009

No. Ayur.-Kha(15)-6/95-IV.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Department of Indian System of Medicine and Homoeopathy, **Senior Lecturer** (Class-II-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, notified *vide* this department Notification No. Ayur.C(Ka)-3- 2/94 dated 1-8-1996 namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Indian System of Medicine and Homoeopathy, **Senior Lecturer** (Class-II-Gazetted) Recruitment and Promotion (First amendment) Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment in Annexure-A.—In Annexure-“A” to the Himachal Pradesh Department of Indian System of Medical and Homoeopathy, Senior Lecturer (Class-II-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1997 :—

For the existing provision against Col.No.17 the following shall be substituted, namely :—

“Every member of service, in view of Provision of Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time shall be exempted from passing the Departmental Examination. However, he shall pass the Departmental Examination for promotion to the post of Principal, failing which he shall not be eligible for promotion to the said post.”

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 अगस्त, 2009

संख्या आयु0-ख (15)-6/95-IV.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या आयु0-सी (क) 3-2/94 तारीख 24-5-1997 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, रीडर, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, रीडर, वर्ग-I (राजपत्रित) सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2009 हैं ।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उपाबन्ध 'अ' का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, रीडर-I (राजपत्रित) सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध 'अ' में:—

स्तम्भ संख्या 17 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 के उपबन्ध के दृष्टिगत, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट होगी । तथापि, उसे प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, ऐसा न होने पर वह उक्त पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा” ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव ।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Ayur.-Kha(15)-6/95-IV dated 11-08-2009 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

AYURVEDA DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th August, 2009

No. Ayur.-Kha(15)-6/95-IV.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Department of Indian System of Medicine and Homoeopathy, **Reader** (Class-I-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, notified *vide* this department Notification No. Ayur.C(Ka)-3-2/94 dated 24-5-1997 namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Indian System of Medicine and Homoeopathy, **Reader** (Class-I-Gazetted) Recruitment and Promotion (First amendment) Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment in Annexure-A.—In Annexure-“A” to the Himachal Pradesh Department of Indian System of Medical and Homoeopathy, Reader (Class-I-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1997 :—

For the existing provision against Col. No.17 the following shall be substituted, namely :—

“Every member of service, in view of Provision of Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time shall be exempted from passing the Departmental Examination. However, he shall pass the Departmental Examination for promotion to the post of Principal, failing which he shall not be eligible for promotion to the said post.”

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 अगस्त, 2009

संख्या आयु0-ख (15)-3/95-IV.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या आयु0-सी (क) 3-2/94 तारीख 16-5-1997 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल

प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, आचार्य, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, आचार्य, वर्ग-I (राजपत्रित) सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2009 हैं ।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उपाबन्ध 'अ' का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, आचार्य वर्ग-I (राजपत्रित) सेवाएं भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 के उपाबन्ध 'अ' में:—

स्तम्भ संख्या 17 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित उपबन्ध रखा जाएगा, अर्थात्:—

“सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय समय पर यथा संशोधित विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा के उपबन्ध के दृष्टिगत, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट होगी। तथापि, उसे प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, ऐसा न होने पर वह प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा” ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Ayur.-Kha(15)-6/95-IV dated 11-08-2009 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

AYURVEDA DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th August, 2009

No. Ayur.-Kha(15)-6/95-IV.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P.Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Department of Indian System of Medicine and Homoeopathy, **Professor** Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, notified *vide* this department Notification No.Ayur.C(Ka)-3- 1/94 dated 16-5-1997 namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Indian System of Medicine and Homoeopathy, **Professor** (Class-I-Gazetted) Services Recruitment and Promotion (First amendment) Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment in Annexure-A.—In Annexure-“A” to the Himachal Pradesh Department of Indian System of Medical and Homoeopathy, Professor Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1997 :—

For the existing provision against Col. No.17 the following shall be substituted, namely :—

“Every member of service, in view of Provision of Departmental Examination, as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time shall be exempted from passing the Departmental Examination. However, he shall pass the Departmental Examination for promotion to the post of Principal, failing which he shall not be eligible for promotion to the post of Principala.”

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला—171002, 28 जुलाई, 2009

संख्या: सिंचाई: 11-9/2007-कुल्लू—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव फाटी शिलीहार तहसील व जिला कुल्लू में पेयजल योजना भुत्तर जल भण्डारण के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	क्षेत्र बिघा/बिस्वा में
कुल्लू	कुल्लू	फाटी	3996/1	0- 08-10
		शिलीहार	7142/1	0-11-16
			6281	0-03-00
			किता-3	1-03-06

संख्या: सिंचाई : 11-151/2005-कुल्लू—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव परगाणू फाटी व कोठी खोखण तहसील व जिला कुल्लू में जल भण्डारण टैंक पेयजल योजना भून्तर के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग कुल्लू हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	क्षेत्र बिघा/बिस्वा में
कुल्लू	कुल्लू	परगाणू फाटी व कोठी खोखण	873/1	0-02-01

शिमला-171002, 3 अगस्त, 2009

संख्या: सिंचाई: 11-18/2008-कांगड़ा—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भोग्रवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना का दाया किनारा के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएवं एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	क्षेत्र हैक्टियरों में
कांगड़ा	इन्दौरा	भोग्रवां	6/2	0-13-20
			7/2	0-57-98
			8/2	0-25-32
			किता-3	0-96-50 है०

शिमला-171002, 03 अगस्त, 2009

संख्या: सिंचाई: 11-90/2008-कांगड़ा.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः बहादपुर, मण्ड-भोग्रवां तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	क्षेत्र	क्षेत्र हैक्टेयर	में
कांगड़ा	फतेहपुर	वहादपुर	896	0	17	16
			881	0	00	52
			882	0	00	22
			883	0	02	04
			965/1	0	00	47
			965/3	0	00	13
			967/1	0	01	26
			1058/1	0	05	72
			1059/1	0	01	48
			2462/1181/1	0	04	72
			2465/1208/1	0	00	70
			1229/1	0	09	20
			Kitta-12	0	43	62

कांगड़ा	इन्दौरा	मण्ड भोग्रवां	970	0	01	14
			969	0	00	81
			965	0	00	33
			964	0	00	77
			963/1	0	00	24
			982/1	0	00	36
			983/1	0	00	70
			985/2	0	01	12
			990/2	0	00	76
			994/1	0	00	09
			994/3	0	00	08
			993/2	0	00	30
			1001/2	0	03	50
			1008/2	0	00	57
			1010/2	0	06	48
			885/1	0	00	30
			883/1	0	01	50
			882/1	0	00	14
			881/2	0	02	92
			879/1	0	00	16
			878/1	0	09	56
			504/1	0	04	16
			511	0	02	13
			510/1	0	01	57
			515/1	0	01	18
			518/1	0	02	72
			517/1	0	01	04
			522/1	0	00	08
			520/1	0	00	72
			521/1	0	00	60
			543/1	0	00	09
			542/1	0	00	16
			541/1	0	00	88
			640/1	0	00	44
			639/1	0	00	08
			545/2	0	04	68
			546/2	0	05	28
			548/2	0	02	80
			560/1	0	01	04
			559/1	0	00	40
			556/1	0	01	28
			555/1	0	02	44
			577/1	0	00	60
			577/3	0	01	50
			576/1	0	00	52
			580/1	0	02	00
			582/1	0	00	32
			581/1	0	01	02

584/1	0	00	55
596/1	0	00	38
605/1	0	01	62
607/1	0	04	06
608/1	0	02	60
609	0	03	80
610	0	02	10
723	0	03	88
724	0	07	88
Kitas-57	1	00	93

शिमला-171002, 03 अगस्त, 2009

संख्या: सिंचाई : 11-16/2008-कांगड़ा.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बहादपुर तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	क्षेत्र हैक्टेयरों में
कांगड़ा	फतेहपुर	बहादपुर	1867/1	0-07-48
			1865/1	0-01-35
			1864/1/1	0-01-00
			1861/1	0-01-95
			1864	0-04-26
			1869/1	0-00-72
			1857	0-06-59
			1848	0-02-12
			1815	0-08-56
			471	0-05-76
			480/1	0-07-26
			585	0-17-80
			586/1	0-01-22

590/1	0-00-16
690/1	0-01-48
691/1	0-01-18
692/1	0-00-28
693/1	0-00-22
694/1	0-01-36
704	0-07-08
702/1	0-00-16
699/2	0-01-34
698/2	0-01-84
669/2	0-00-25
668/2	0-00-83
667/1	0-00-28
666/1	0-00-09
762/1	0-00-21
765/2	0-00-88
768/2	0-02-76
770/1	0-01-24
780/1	0-00-12
781/1	0-00-52
788/2	0-00-04
797/2	0-00-92
802/1	0-01060
815/1	0-00-40
814/1	0-01-36
813/1	0-00-28
819/1	0-00-56
1068/2	0-09-00
<hr/>	
किता-41	1-06-49 है०

शिमला-171002, 13 अगस्त, 2009

संख्या सिंचाई 11-91/2008-कांगड़ा.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव इन्दपुर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है।

4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र	क्षेत्र हेक्टेयर	में
कांगड़ा	इन्दौरा	इन्दपुर	991/1	0	02	31
			992/1	0	02	79
			997/2	0	02	33
			998/2	0	08	80
			999/1	0	07	33
			1000/1	0	06	12
			1095/1	0	00	07
			1096/1	0	00	60
			1099/1	0	05	00
			1100/2	0	03	67
			1102/1/1	0	00	20
			1898/1	0	03	75
			1899/1	0	01	19
			1900/1	0	03	42
			2038/1	0	01	48
			2040/2	0	06	24
			2069/1	0	00	22
			2072/2	0	06	12
			2039/2	0	00	63
			1881/1	0	05	27
			1841/2	0	04	00
			1842/2	0	07	44
			1836/2	0	12	40
			2250/2	0	11	02
			2165/1	0	03	72
			2165/2	0	02	09
			2127/2	0	00	61
			2027/2	0	02	88
			2147	0	01	86
			2146/2	0	05	21
			2070/2	0	01	66
			1085/2	0	02	96
			1092/2	0	04	08
			2128/2	0	04	98
			6102/2	0	23	00
			5930/2	0	14	66
			5931/2	0	06	51
			5932/2	0	13	77
			5932/4	0	07	35
			5933/2	0	07	20
			5812/2	0	02	50
			5813/2	0	00	50
			5815/2	0	06	37
			5818/2	0	05	30

5819/2	0	01	32
5822/2	0	04	35
5823/2	0	06	45
5842/2	0	00	42
5843/2	0	02	98
5650/2	0	01	20
5863/2	0	03	57
5864/2	0	02	19
5866/2	0	00	60
5867/2	0	01	62
5741	0	03	30
5725/1	0	00	84
5726/1	0	00	81
5729/2	0	04	81
5731/2	0	03	15
5730/3	0	05	30
5743/1	0	00	18
5744/1	0	00	26
5760/2	0	06	51
5648/2	0	02	47
5649/2	0	01	75
2248/2	0	02	19
2249/1/2	0	01	95
2255/2	0	04	50
2258/2	0	06	65
2261/2	0	05	76
2262/1	0	01	48
2263/2	0	01	30
2266	0	02	19
Kitta-73	3	00	00

शिमला-171002, 13 अगस्त, 2009

संख्या सिंचाई 11-67/2008-कांगड़ा.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल पनियाला मौजा मन्दौली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएवं एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है।

4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	महाल व मौजा	खसरा नं०	क्षेत्र / हेक्टेयर में
कांगड़ा	इन्दौरा	पनियाला / मन्दोली	677/1/2	0-01-87
			673/2	0-04-67
			677/1	0-00-22
			678/1	0-00-15
			1256/1	0-00-12
			1256/2	0-00-28
			1259	0-01-56
			1265/2	0-15-07
			1265/3	0-34-73
			1292	0-14-26
			1293	0-09-48
			1299	0-00-30
			किता-12	0-83-03 है०

शिमला-171002, 07 जुलाई, 2009

संख्या: सिंचाई: 11-62/2008-कुल्लू—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः फाटी दियार कोठी कोट कण्डी, तहसील व जिला कुल्लू में पम्प हाऊस उठाऊ पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डी, जिला मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग मण्डी, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र / बीघा / बिस्वा में
कुल्लू	कुल्लू	भेड़ुफार्म	2911	0-01
			2725	0-3
			2793	0-03
			किता-3	0-17

शिमला-171002, 01 जुलाई, 2009

संख्या सिंचाई: 11-15/2007-कांगड़ा.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल घण्डरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना का किनारा के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना फतेहपुर को उक्त अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है ।

4. भूमि रेखांक, का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, शाहनहर परियोजना, फतेहपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला	तहसील	महाल	खसरा न०	क्षेत्र (हैक्टेयर में)
कांगड़ा	इन्दौरा	घण्डरा	591/1	0-31-20 है०

शिमला-171002, 01 जुलाई, 2009

संख्या: सिंचाई 11-26/2009-शिमला.—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव रियाणा दोची तहसील ठियोग जिला शिमला में उठाऊ पेयजल योजना पम्प हाउस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न०	क्षेत्र		
				वीघा	विस्वा	विस्वासी
शिमला	टियोग	रियाणा	200	0	05	37
			201	0	07	07
			202	0	23	18
			203	0	32	80
			Kittas-4	0	68	42

शिमला-171002, 30 जून, 2009

शुद्धि पत्र

संख्या: सिंचाई: 11-17/2009-कुल्लू—इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 09-04-2009 जोकि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 के अन्तर्गत नामतः गांव बारी बिहाल, फाटी, खराहल, कोठी कायस तहसील व जिला कुल्लू में पम्प हाऊस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने के लिए जारी की गई है, में निम्न शुद्धि की जाती हैं :-

1. "अधिसूचना के पृष्ठ-1 (पैरा-4) में भू-अर्जन समाहर्ता, कुल्लू हिमाचल प्रदेश के स्थान पर उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कुल्लू जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश पढ़ा जाए ।
2. उपरोक्त वर्णित अधिसूचना के पृष्ठ-2 क्रम संख्या-6 पर भू-अर्जन अधिकारी लोक निर्माण विभाग कुल्लू के स्थान पर भू-अर्जन समाहर्ता एवं उप-मण्डल अधिकारी कुल्लू पढ़ा जाए ।

शिमला-171002, 27 जून, 2009

संख्या: सिंचाई 11-57/2008-बिलासपुर—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव दवट मजारी तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर में पम्प हाऊस में जाने के लिए रास्ता के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र बीघे-विस्वे में
बिलासपुर	घुमारवीं	दवट/मजारी	1484/588/2	0-06

शिमला-171002, 23 जून, 2009

संख्या: सिंचाई : 11-44/2008-कांगड़ा.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल पेयजल योजना राम नगर-श्यामनगर के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, जिला कांगड़ा, को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र/वर्ग मी० में०
कांगड़ा	धर्मशाला	महाल श्यामनगर	548/1	119.25 वर्ग डै० मी०

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव ।

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 20th August, 2009*

No. HFW-B (F) 2-3/2006.—In pursuance to Sections 3 and 7 of 'The Himachal Pradesh Private Medical Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2006,' the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the Fee Structure in respect of BDS courses in Private Un-aided Dental Colleges in Himachal Pradesh, for the academic session commencing from the year 2009-10, as per the recommendations made by the Admission & Fee Committee, as under:—

State Quota (50%)

1. For the students admitted from HPCPMET merit, fee will be Rs. 51,000/- per annum at par with the second year BDS students who were admitted last year.

2. For the students admitted after exhausting merit list of HPCPMET as per procedure prescribed under clause 5 (a) to 5(d) of chapter V(A) "Admission Procedure" of the Prospectus, fee will be Rs. 75,000/- per annum.
3. For the students admitted after exhausting merit list of HPCPMET and the procedure prescribed under clause 5 (a) to 5(d) of chapter V(A) "Admission Procedure" of the Prospectus for the year 2009-10 i.e. under clause 5(e) of chapter V(A) "Admission Procedure" fee will be Rs. 1,25,000/- per annum.

Management Quota (50%)

1. For the students admitted from HPCPMET merit or CBSE Pre Medical Examination merit fee, will be Rs. 1,75,000/- per annum.
2. For the students admitted on the basis of 10+2 qualifying marks fee, will be Rs.2,15,000/- per annum.

The Clause 5 (a) to 5(e) Chapter V(A) of the Prospectus of HPCPMET for the year 2009-10 is reproduced below:

"5. However, in case the seats in the general category (50% state quota) remain vacant even after exhausting the merit list of the HPCPMET the remaining seats will be filled-up by adopting the following admission procedure in private unaided Medical/ Dental Colleges:

- (a) *1st preference will be given in order of final merit of main CBSE Pre-Medical/Dental entrance examination of 2009 of bonafide Himachali candidates.*
- (b) *2nd preference will be given in order of Merit of +2 qualifying examination of those bonafide Himachali candidates who have also appeared in HP-CPMET 2009.*
- (c) *3rd preference will be given in order of merit of +2 qualifying examination of bonafide H.P. candidates who have passed +2 examination from Govt./ recognized school in HP with atleast 50% marks in +2.*
- (d) *4th Preference will be given in order of merit of +2 qualifying examination of those bonafide HP candidates who have passed +2 examinations from any Government/ recognized school in India with at least 50% marks in +2.*
- (e) *In case the seats in the State Quota remain vacant even after exhausting the candidates available under the 4th preference then the candidates at the top of merit list of Management Quota as per the final merit of the HP-CPMET, will be converted to the State Quota Seats to fulfill the remaining vacancies in the State Quota. In such a case the candidates so converted shall be charged the fee payable by the State Quota candidate. Subsequent resultant vacancies in the Management Quota Seats after converting the top merit holders in Management Quota to the State Quota will be filled up from the waiting list of Management Quota Seats."*

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

**BEFORE THE DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, HAMIRPUR,
DISTRICT HAMIRPUR , HIMACHAL PRADESH**

C. C. No. 04/2007 (HMR)

**PROCLAMATION FOR DISPOSAL OF COMPLAINT UNDER SECTION 12 OF CONSUMER
PROTECTION ACT, 1986**

In the matter of :

Tara Devi

.. *Complainants(s)*

Versus

H. C. Pathak & Others
(s)

.. *Opposite party*

Notice to :

OP-5. Baldev Singh S. H. O. Police Station Bhoranj at present Police Station Sadar
Una, Tehsil & District Una (H. P.).

OP-6. Kuldeep Singh H. C. Police Station Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

Whereas a complaint has been filed by the complainant against you under section 12 of the Consumer Protection Act, 1986. This Forum is satisfied that you can not be served through ordinary way and you are evading the service of summons intentionally. You are hereby required to give your version of the case in this Form of the written reply on 4-09-2009 at 10.00 A.M. in the court room of the Additional District Magistrate (ADM) Hamirpur, District Hamirpur, H. P. You must also be prepared to produce all the documents upon which you intend to rely in support of your version on the fixed date of hearing.

Take notice that in default of your appearance on the day before mentioned the case shall be heard in your absence.

By order of this forum

Issued today on dated August 13, 2009 under my hand and seal of this Forum.

Seal.

D. D. SHARMA,
President,
District Consumer Disputes Redressal Forum,
Hamirpur Forum Bilaspur & Una,
District Una (H. P.).

ब अदालत भू-सुधार अधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री गंगा राम सुपुत्र श्री किरपा राम, निवासी जाहू खुर्द, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश आदि वादीगण।

बनाम

1. श्री मेहर सिंह, 2. श्री ध्यान सिंह सुपुत्र द्रौम्पती समस्त निवासीगण टीका जाहू खुर्द, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर प्रतिवादीगण।

विषय.—दरुस्ती खसरा गिरदावरी खाता नं० 327, खतौनी नं० 360, खसरा नं० 22 मिन, रकबा तादादी 0क-5म टीका जाहू खुर्द, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर।

उपरोक्त उनवानबाला में उपरोक्त दर्शित प्रतिवादीगण को कई बार समन द्वारा तलब किया गया किन्तु प्रतिवादीगण की तामील सही ढंग से न हो पा रही है। अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 4-9-2009 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगी।

आज दिनांक 23-7-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

भू-सुधार अधिकारी,
भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत भू-सुधार अधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री जीवन दास सुपुत्र श्री कांशी राम, निवासी जाहू खुर्द, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश आदि वादीगण।

बनाम

1. सरला देवी सुपुत्री श्री कांशी राम, 2. मूल राज सुपुत्र, 3. जीतू सुपुत्र, 4. मिकू सुपुत्र, 5. करमी देवी सुपुत्री, 6. आशा देवी सुपुत्री, 7. अनीता सुपुत्री श्री विक्रम सुपुत्र श्री कांशी राम, 8. राजू राम सुपुत्र श्री कांशी राम समस्त निवासीगण टीका जाहू खुर्द, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर। प्रतिवादीगण।

विषय.—दरुस्ती खसरा गिरदावरी खाता नं० 334ए, खतौनी नं० 366, खसरा नं० 308, रकबा तादादी 1क-8म टीका जाहू खुर्द, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर।

उपरोक्त उनवानबाला में उपरोक्त दर्शित प्रतिवादीगण को कई बार समन द्वारा तलब किया गया किन्तु प्रतिवादीगण की तामील सही ढंग से न हो पा रही है। अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 4-9-2009 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगी।

आज दिनांक 23-7-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
भू-सुधार अधिकारी,
भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री सुर्जन सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती मीना डोगरा पत्नी स्व० श्री देव राज, गांव कैहरवीं, डा० बलोह, तपा बमसन, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश आदि प्राथिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती मीना डोगरा पत्नी स्व० श्री देव राज ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की सोनिका का जन्म दिनांक 09-05-1983 को गांव कैहरवीं में हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत ढनवाल व कैहरवीं में जन्म तिथि पंजीकृत नहीं हुई है जिसके पंजीकरण बारे ग्राम पंचायत कैहरवीं को आदेश दिए जाएं।

इस नोटिस/इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को सोनिका की जन्म तिथि के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज इस अदालत में दिनांक 14-9-2009 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्राथिया के शपथ-पत्र के आधार पर प्राथिया की पुत्री सोनिका की जन्म तिथि के पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत कैहरवीं को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-08-2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुर्जन सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, ऊना, जिला ऊना, हि. प्र

अधिसूचना

ऊना, 2009

क्रमांक खाद्य मूल्य सूची-08/-—पिछले सभी आदेशों एवं अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए तथा हि.प्र. जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 की धारा 3(1) ई के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, के० आर० भारती, जिला दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना निम्नलिखित आवश्यक वस्तुओं के

प्रत्येक के समक्ष दर्शाये गये मूल्य सभी करों सहित निर्धारित करता हूं। कोई भी व्यापारी तथा निर्माता निर्धारित मूल्य से अधिक प्राप्त नहीं करेगा।

क्रमांक	अनुसूची संख्या	वस्तु का नाम	समस्त करों सहित परचून मूल्य
1	2	3	4
1	12	मीट बकरा, मुर्गा व मछली की दरें	रुपये
		1. मीट बकरा कच्चा प्रति किलो	120.00
		2. मीट मुर्गा ब्राइलर ड्रैस्ड प्रति किलो	90.00
		3. मुर्गा जीवित प्रति किलो	70.00
		4. मछली ग्रेड-1 प्रति किलो कच्ची	58.00
		5. मछली ग्रेड-2 प्रति किलो कच्ची	50.00
		6. मछली तली हुई (तलने के उपरान्त) प्रति किलो	100.00
2	13	1. अण्डे थोक 3 प्रतिशत व परचून 6 प्रतिशत इस लाभांश के अतिरिक्त एक प्रतिशत टूट फूट देय होगी	
3	17	होटल/ढाबों में परोसा जाने वाला खाना, सब्जियों इत्यादि	
		1. पूरी खुराक दाल सब्जी व चार चपाती सहित सादा (चार चपाती से उपर व फ्राई दाल के अतिरिक्त भाव लिए जायेंगे)	25.00
		2. स्पेशल सब्जी चने, गोभी, पालक, मटर, भिण्डी आलू मटर राजमाह व सफेद चने प्रति प्लेट	25.00
		3. मटर पनीर व पालक पनीर प्रति प्लेट	30.00
		4. मीट पका हुआ प्रति प्लेट	40.00
		5. चिकन पका हुआ व चिकन करी प्रति प्लेट	40.00
		6. दाल फ्राई प्रति प्लेट	20.00
		7. तवा चपाती प्रति	2.00
		8. तन्दूरी चपाती प्रत्येक	3.00
		9. परोठा भरा हुआ आचार सहित	10.00
		10. दो पूरी चने सहित प्रति प्लेट	15.00
4	18	दूध दही व पनीर के मूल्य	
		1. हलवाईयों द्वारा बेचा जाने वाला कच्चा दूध (खुला दूध) प्रति लीटर	24.00
		2. दूध पैकेट सभी ब्रांड का निर्माता द्वारा पैकेट पर छपी दर	
		3. दही प्रति किलो	30.00
5	20	ठण्डे पेय पदार्थ	
		1. बोतल वाले पेय : कम्पनी द्वारा निर्धारित बोतलों पर अंकित मूल्य/जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित लाभांश में से जो भी कम हो।	

(क) उक्त निर्धारित मूल्य समस्त जिला ऊना में हिमाचल प्रदेश राजपत्रित असाधारण में प्रकाशित होने की तिथि से एक माह तक लागू रहेंगे। सभी परचून ढावा, होटल, मीट बिक्रेता, अण्डे मछली बेचने वाले अपनी अपनी दुकानों के बाहर ग्राहकों की जानकारी हेतु मूल्य सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे

जोकि स्पष्ट रूप में देवनागरी लिपि में लिखित होना आवश्यक होगी । दुकानदार/ भागीदार एवं प्रबन्धक के द्वारा हस्ताक्षरित होनी आवश्यक होगी ।

(ख) प्रत्येक दुकानदार को ग्राहक के मांगने पर कैशमीरो देना अनिवार्य होगा ।

आदेश द्वारा,
के० आर० भारती,
जिला दण्डाधिकारी।

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA – 171 001

NOTIFICATIONS

Shimla, the 10th August, 2009

No. HHC/15-37/JUS/ACCTTS/2008.—It is hereby notified that Hon'ble Mr. Justice Jagdish Bhalla, Chief Justice of this Court, who has been transferred as Chief Justice of Rajasthan High Court vide Government of India, Ministry of Law and Justice Notification No.K.11017/5/2009-US.II dated 3rd August, 2009 ceased to perform the duties of the office of the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh on and with effect from Monday, August 10, 2009, forenoon.

Shimla, the 10th August, 2009

No.HHC/15-38/JUS/ACCTTS/2008.—It is hereby notified that Hon'ble Mr. Justice Ram Bhawan Misra, Judge, High Court of Himachal Pradesh, pursuant to Notification No.K.11019/2/2009-US.II dated 7th August, 2009 issued by the Government of India, Ministry of Law and Justice, New Delhi, has assumed the charge of the office of the Acting Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh in the forenoon of 10th August, 2009.

Shimla, the 11th August, 2009

No. HHC/Admn.1(18)/78-X- In partial modification of this Registry Office Order No.HHC/Admn.1(18)/78-IX-11426-34, dated 21-5-2008 and in exercise of the powers vested in him under Article 229 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to order the following re-designation and allocation of work amongst the Registrars :

1. Shri Dharam Chand Chaudhary, presently Principal Secretary to Hon'ble the Chief Justice-cum-Registrar (Vigilance) is re-designated as Registrar (Vigilance);
2. Shri Virender Singh, presently Registrar (Inspection) is re-designated as Principal Secretary to Hon'ble the Chief Justice-cum-Registrar (Inspection).

By Order,
Sd/-
Registrar General.